प्रस्तावना

E-Governance को लागू करने के लिये वित्तीय आवश्यकता को नकारते हुए उपलब्ध संसाधनो का उपयोग किया गया। सामान्यतः E-Governance हेतु सम्पन्न अधोसंरचना (Infrastructure) व बाह्य संसाधनो (Outsourcing) के सहयोग की परिकल्पना की जाती है। परन्तु विभाग ने अन्य शासकीय संस्था के सहयोग से निःशुल्क (Free of Cost) इस परिकल्पना को साकार किया है।

इस व्यवस्था से क्षेत्रीय स्तर पर स्थित महाविद्यालय को इस कार्य में संलग्न कर Information को Electronically व्यवहार मे लाने की परिपाटी प्रचलन में ला सके। इसका व्यवहारिक उदाहरण Website की प्रतिदिन Hitting से सहजता से लगाया जा सकता है।

शीर्षस्थ कार्यालय में जानकारी का संकलन क्षेत्रीय स्तर पर स्थित महाविद्यालय से होता है। पूर्व में जानकारी Hard copy में डाक से भेजी जाती थी। जिसके संकलन में अत्यधिक श्रम लगता था। इस प्रक्रिया के निवारण (Solution) हेतु विभागीय स्तर पर कार्य की आवश्यकतानुसार Software विकसित किये गये। जिसे Website पर उपलब्ध कराते हुए जानकारी अद्यतन करा कर E-mail से प्राप्त किया गया, जिससे संकलन त्वरित हो सके। इस प्रयोग में सफलता पाई व Postal Expenditure कम किया गया। शासकीय स्तर पर समय व श्रम की बचत हेतु, शासन स्तर की योजनाओं व विभागीय कार्य की सुलभता हेतु निःशुल्क Software विकसित किये गये।